

## असाधारगा EXTRAORDINARY

भाग II—वण्ड 3—उप-वण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई बिल्ली, सोमबार, मार्च 25, 1996/चंझ 5, 1918 No. 120] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1996/CHAITRA 5, 1918

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहबारिता विभाग)

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1996

सा.का.निः 148(श्र).—केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी श्रिधिनियम, 1984 (1984 का 51) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहुराज्य सहकारी सोमाइटी (विशेषाधिकार, संपत्ति श्रार निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा, परिसमापन श्रीर डिकियों, श्रादेशों श्रीर विनिश्चयों का निष्पादन) नियम, 1985 में संशोधन करने के लिए निम्निखित नियम बनाती है, ग्रर्थात:——

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य महकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, संपत्ति ग्रीर निधिया, लेखा परीक्षा, परिसमापन ग्रीर डिकियों, ग्रादेणों ग्रीर विनिश्चयों का निष्पादन (संशोधन) नियम, 1996 है।

- (2) ये राजपत में प्रकाणन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
- 2. बहुराज्य सहकारों मोलाइटी (त्रिगेषाधिकार, संपत्ति श्रीर निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा परिसमापन और डिकियों, श्रीर स्रादेशों श्रीर विनिम्लयों का निपादन) नियम, 1985 में, नियम 10 में उपनियम (3) के स्थान पर निम्तिशिखन उपनियम रखा जाएगा, श्रायांत :—
- "(3) ऋण के प्रतिसंदाय की अवधि जननी होगी जिन्नी उपविधियों में दी गई हो किनु मकान कय/क्षेटों के निर्माण/कम ने अवधित ऋगों की दगा में 10 वर्ष और किसी अन्य प्रयोजन के लिए 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, परन्तु कर्मचारी सहकारी बचन और प्रत्यय सोगाइटियों की दगा में ऋण की अवधि कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से अधिक नहीं होगी"।

[सं. एल--11012/4/92-एल एंड एम] मोहन कोंदा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजयत में साजा नि. मं. 812(प्र) तारीख 28 अक्तूबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 1996

GSR 148 (E)]:—In exercise of the powers conferred by Section 109 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) (Amendment) Rules, 1996.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts Audit Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985, in rule 10, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
- "(3) The period of repayment of the loan shall be as provided in the bye-laws, but shall not exceed ten years in case of loans related to construction/

purchase of house/flats and five years for any other purpose: Provided that in case of employees' co-operative thrift and credit societies, the period of loan shall no exceed the date of retirement of the employee.".

[No. L-11012/4/92-L&M MOHAN KANDA, Jt. Secy.

F. Note:— The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 812(E), dated the 8th October, 1935.